جاننا چاہتا ہوں اور مجھے اس کا جواب دیکر نہ صرف یہ کہ مجھے مطمئن کریں بلکہ ملک کے تمام وفادار شہریوں کو مطمئن کریں۔ یہ ملک کے اوپر ایک عظیم چنوتی اور بڑا نازک وقت آیا ہے اس کو ہم سیاسی مصلحتوں پہ قربان نہ کریں بلکہ اپنی ذاتی خود غرضیوں کو قربان کرتے ہوئے ملک اور قوم کے تحفظ کے سلسلے میں ہر طرح کی قربانی ذاتیات اور جماعت سے اوپر اٹھ کر دیں۔ یہ ہمارا ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے کو لازم ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ [illegible]

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Hon. Minister has rightly exposed this Convention. It appears that this piece of document of the Convention is only ornamental; it is a showpiece. The hon. Minister did mention that this Convention does not include any clause for extradition. May I know from the hon. Minister in view of the latest position where the Memon fugitives have been harboured by Pakistan Government, whether the Government of India will move the forthcoming SAARC Summit to see that a clause is included in this Convention whereby the element of extradition is included. Further, may I know from the hon. Minister whether they have raised this in the international for a suc as the United Nations, the Commonwealth and the Non-aligned Movement, to bring pressure on Pakistan to see that the fugitives are handed over to India?

SHRI R. L. BHATIA: Madam, first of all, let me make it cear. I want to correct the impression which Mr. Gujral got out of my statement. I stand by what Mr. Chavan had said and what the Foreign Minister, Mr. Dinesh Singh had said. There is no variance at all. Therefore, no inference has arisen out of the discussion here that my statement is at variance.

The second point which Mr. Gujral had raised was — he was emphasising it again and again — whether we have been able to convey to our SAARK friends who have signed this Convention. I say 'Yes'. We have informed.

In regard to the point made by Mr. Vishvjit Singh as to whether we have informed the other Governments also, yes; we have informed all our friends in the world in regard to what had happened.

Another question was about hijacking. I would like to point out that there is no extradition treaty between India and Pakistan. We are demanding the return of the hijackers, but they say that in accordance with their own laws, they will deal with the hijackers and that they are prosecuting them As far as the point made by Mr. Azmi is concerned, about our Prime Minister going to Bangladesh, we have talked to the Bangladesh Government in regard to the arrangements there. I can assure you that the Bangladesh Government has informed us that they will take all necessary steps.

Madam, I move:

"That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to."

*The question was put and the motion was adopted*

## RESOLUTION RE. RECOMMENDATIONS OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): Madam, I beg to move the following Resolution:

That this House approves the recommendations made in paragraphs 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50 contained in the Third Report of Railway Convention Committee, 1991, appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance which was laid on the Table of the Rajya Sabha on 23-2-1993.

Madam, by a Resolution adopted in the Lok Sabha on 16th September, 1991, and concurred in by the Rajya Sabha on 17th September, 1991, the Railway Convention Committee, 1991 was constituted on 25th November, 1991. The Committee was appointed to review the rate of dividend which is at present payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance and make recommendations thereon. The Ministry of Railways submitted an interim memorandum requesting the Committee to permit continuance of the finance arrangements between the Railways and the General Finance for the year 1993-94 by and large on the same basis as adopted for the year 1992-93 in the manner recommended by the Railway Convention Committee (1991) in their First Report, pending their final recommendation for the Eighth Plan for which memorandum to the Committe has also been submitted. The Railway Convention Committee, 1991, have considered the interim memorandum and have, as an interim measure, by and large, agreed to the proposals made therein by the Ministry of Railways, except that for the year 1993-94, dividend to General Revenues may be paid at an enhanced rate of 7 per cent on the entire capital invested on Railways from General Revenues irrespective of the year of investment, as against the existing rate of 6 per cent on the capital invested on Railways upto 31st March, 1980, and at 6.5 per cent on the capital invested thereafter.

With these words, I commend the Resolution for the cosideration of this House.

The question was proposed.

**श्री सुन्दर सिंह भण्डारी** (राजस्थान) : उपसभापति जी, यह जो प्रस्ताव रखा गया है, इससे देश की सामान्य जनता पर और अर्थ-व्यवस्था पर एक परिणाम होता है।

अब रेट आफ डिविडेंड बढ़ा दी गई है। उस पर भी जो पहले 6 प्रतिशत थी, या बाद में उस पर किस पर साढ़े छह प्रतिशत थी, स्वाभाविक बात है कि रेलवेज इस समय काफी आर्थिक संकट में से गुजर रही है। लेकिन आर्थिक संकट के इस बोझ को लोगों को ट्रांसफर करने की बजाए, सरकार को अपने स्वयं के साधनों का बैटर मैनेजमेंट करने की आवश्यकता थी। जो बैंक स्कैम हुआ है, उसमें भी 400 करोड़ रुपया रेलवे का फंसा हुआ है और इस कारण से और भी मुश्किल में पड़ी हैं रेलवे। अपनी व्यवस्था बनाने में और यह पहला अवसर है कि जब 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक किराया-यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाने पर हम मजबूर हुए हैं। 1848 करोड़ रुपया इससे लोगों पर नया बोझ आया है।

मेरा यह निवेदन है कि इस सारी अव्यवस्था के कारण ही जो बड़े टैक्स-फ्री बांड सरकार, रेलवे की तरफ से जारी किये गये थे 10.5 प्रतिशत रेट पर, लोगों ने उसमें भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। पिछली बार जो यह कहा गया था कि बारह हजार करोड़ रुपया हम पब्लिक से वसूल कर लेंगे, इस बात का आंकड़ा दिया गया है कि केवल 10.5 करोड़ रुपया ही पब्लिक से मिल पाया है, और यही वजह है कि इन नीतियों के आधार पर लोगों पर किराया बढ़ाने की, माल किराया बढ़ाने की नौबत पैदा हुई है।

सरकार को यह चाहिए था कि बजाए इसके कि रेट ग्राफ डिविडेंड बढ़ाते या माल भाड़ा बढ़ाते सरकार को बजेटरी एलोकेशन प्लान की तरफ से जो कम किया गया है, आज के विशेष हालात को देखते हुए उन्हें इस कमी को नहीं करना चाहिए था। तो फिर रेल को अपनी व्यवस्था सुधारने का अवसर मिल जाता।

1253 करोड़ रुपया इस साल इस डिविडेंड के आधार पर उन्हें देना है। सरकार इस समय यह व्यवस्था कर सकती थी कि बजाए इसके कि इसका बोझा लोगों पर जाए, सरकार एक साल के लिए डिविडेंड पेमेंट वेव कर देती, तो यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाने की यह नौबत पैदा नहीं होती। भाड़ा भी कम मिलता जा रहा है और अभी भी रेलवे इस बात की व्यवस्था नहीं कर पाई है कि जो सामान ट्रकों में जाता है, वह फिर से रेलवे को प्राप्त होने लगे। उसकी वजह यह है कि लोगों को रेलवे की डिलिवरी पर या माल को पहुंचाने पर समय कितना लिया जाएगा, यह अभी तक भरोसा नहीं है और इसीलिए ट्रक के आधार पर माल का जाना बदस्तूर जारी है, बावजूद इसके कि कुछ क्विक लिंक एक्सप्रेस भी चलाई गई है। लेकिन इस सब के बावजूद जो रेलवे को लाभ मिलना चाहिए या भाड़े में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए वह नहीं हुई है। अभी भी इस माल भाड़े के मामले में या माल को लाने ले जाने के मामले में रेलवे लोगों के मन में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसका भरोसा पैदा नहीं कर पाई है। यह भी एक वजह है कि लोग प्वाइंट टू प्वाइंट डिलिवरी या स्थान पर माल पहुंचाने के लिए ज्यादा पैसा देकर ट्रकों का इस्तेमाल करना पसंद करते है बनिस्बत रेलवे के। कोयला और लोहा अगर ये दोनों चीजें छोड़ दी जाएं तो पता नहीं गुड्स ट्रैफिक में हमारी कुछ अर्निंग होगी भी या नहीं होगी, यह एक संदेह की बात खड़ी होती है। इसलिए इन सब बातों के लिए बेटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। कोयला सब से बड़ा इस्तेमाल करने वाला कमोडिटी होने के बाद भी कोयला कंपनियों में और रेलवे में हमेशा इस बात का विवाद चला करता है कि दोषी कौन है। रेलवे कोयला कंपनियों पर दोष लगाती है और कोयला कंपनियां रेलवे पर दोष लगाती हैं कि हमको समय पर वैगन प्राप्त नहीं होते। आपका यह कहना है कि वैगंस को लोड करने में देरी होती है। यह विवाद कई वर्षों से चल रहा है। अभी तक इसका कोई समाधानकारक रास्ता नहीं निकल सका है। इसलिए इस पहलू पर यह जो दो कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन है कम से कम इसी पर कंसेंटरेट करके रेलवे अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है। अभी भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में पूरे कदम नहीं उठाए गए। इस बात की शिकायतें हैं कि जो इंजन हमारे पास हैं उनका ठीक से पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता। वे फालतू पड़े रहते हैं और कई जगहों पर डीजल और इलैक्ट्रिफिकेशन की अधूरी व्यवस्था होने के कारण दुगुनी मात्रा में इंजनों की आवश्यकता पड़ती है। बेकार इंजनों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब ये चीजें एफीसिएंसी लाने के लिए यूटिलाइजेशन एसेट्स

का ज्यादा अच्छा हो इसके लिए जरूरी है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि रेलवे के फाइनांसेज में सुधार होगा और जो रेलवे कनवेंक्शन कमेटी ने अनेकों सुझाव दिए हैं उनका पालन करने में आसानी होगी।

मुझे अफसोस है एक्सीडेंट्स के मामले में आंकड़े सही नहीं प्रकट किए जाते और विशेष कर जहां कि रेलवे सेफ्टी के कानून में टकराव आता है उतनी ही बातों का उल्लेख होता है। रेलवे सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जिन घटनाओं को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, न उनकी गिनती होती है, न उसके कारण जो रेलवे ट्रैफिक में डिस्लोकेशन या पैसेंजरों को जो उसके कारण तकलीफें पैदा होती हैं, यार्डस में गड़बड़ियां होती हैं, वर्कशाप्स में छोटे-बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इन सब की गिनती लोगों के पास पहुंच नहीं पाती। इस लिए इस तरफ ध्यान दिया जाए। एक्सीडेंट्स का भी जब सवाल आता है तो पसेंजर ट्रेंस के एक्सीडेंट्स की चर्चा ज्यादा होती है, गुडस डीरेलमेंट्स या गुडस ट्रेंस के एक्सीडेंट्स का उल्लेख नहीं होता हालांकि उनकी वजह से रेलवे को बहुत बड़ी मात्रा में कंपेंशेशन देना पड़ता है। ट्रैफिक जाम रहता है और बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं।

मेरा यह निवेदन है कि इन सारी बातों पर दोबारा विचार किया जाए और ये जो रेट आफ डिविडेंट बढ़ाने का प्रस्ताव है इसको सरकार वापस ले। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]**

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)** : श्री प्रभाकर बी० कोरे : अनुपस्थित

श्री ईश दत्त यादव : अनुपस्थित।
चौधरी हरि सिंह : अनुपस्थित।
प्रो० सौरीन भट्टाचार्य : अनुपस्थित।
श्रीमती सत्या बहिन : अनुपस्थिति।

I think something is wrong with the monitor.

**श्री राम नरेश यादव** (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, रेलवे के संबंध में विशेष रूप से कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात अपनी जगह सही है कि अभी भी रेलवे के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है और इतना बना हुआ है कि जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। महोदय, जबकि सरकार की यह नीति है कि हम क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए रेलवे जैसे विभाग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है और इसलिए देश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय रेलवे मंत्रीजी ने पिछले बजट भाषण में कहा था और यह बात इसमें भी है कि जो देश के पिछड़े क्षेत्र हैं उनके संबंध में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनके लिए कुछ ऐसी योजनायें हों जिससे कि उनकी विषमतायें धीरे-धीरे कम की जा सकें। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इस मामले में बहुत उपेक्षित रहा है और उस संबंध में सरकार का ध्यान जिस तरह से जाना चाहिए उस तरह से ध्यान नहीं गया है। महोदय, अभी कुछ देर पहले भी मैंने इस सवाल को उठाया था और फिर कहना अपना उत्तरदायित्व समझता हूं जिससे कि आपको उत्तर देने में आसानी हो और यह इसलिए जरूरी है कि हमारे पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर और देवरिया—ये ऐसे जिले हैं कि जहां के लोग दूसरी जगह जाकर श्रम करते हैं और अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। महोदय यह,

है हमारे यहां की गरीबी और यह इसलिए है कि यह छोटी लाइन सन् 1908 से चली आ रही है लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है और इसी कारण से जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पा रहा है और जब न इंडस्ट्री होंगी, न दूसरे विकास के काम होंगे, न निर्माण के काम होंगे और न कुटीर उद्योग धंधे वहां होंगे तो मजबूर होकर खेती पर अधिक बोझ पड़ता है तो उसे लोग कहां तक बर्दाशत करेंगे? मजबूर होकर वे बाहर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और इसी कारण बंबई, मद्रास, कलकत्ता हों या दिल्ली हों, इन बड़े शहरों पर बोझ पड़ता है और उससे अनेक कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि वह जिला ऐसा है, वह अंचल ऐसा है जहां पर कि बुनकर बहुल क्षेत्र है। महोदय, घोसी से इधर मबारकपुर का वह क्षेत्र बुनकर बहुल इलाका है उसके लिए भी जो सामान वह बनाते हैं, धोतियां बनाते हैं, साड़ियां बनाते हैं और जो हैंडलूम्स के उद्योग हैं उनका जितना विकास होना चाहिए, वह उस आधार पर नहीं हो पाता है क्योंकि वहां अच्छे आवागमन के साधन नहीं हैं। वहां जो मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। उस प्रश्न की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह वही प्रश्न है छोटी लाइन के बारे में ऐसे चलती है, हमारे विरोधी दल के नेता भी बैठे हैं, ऐसे चलती है... **(व्यवधान)**

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : (उत्तर प्रदेश) : वे छोटी लाइन में नहीं चलते हैं।

**श्री राम नरेश यादव** : कभी अगर उसमें बैठने का मौका मिले तो जो शाहगंज से आजमगढ़ की दूरी दूसरी ट्रेनों से 30 मिनट में पूरी की जा सकती है, वह दूरी तीन घंटे से कम में नहीं पूरी होगी। यह स्थिति है लिल्ली घोड़ी सी। वह बरसात में जो होती है, हरी-हरी घास सी दिखाई पड़ती है, वैसे ही धीरे-धीरे चलती है। इसलिए हम लोग बहुत दिनों से इस बात का प्रयास करते आ रहे हैं, मांग भी करते आ रहे हैं कि इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जाए। सन् 1977 से यह मामला हमने उठाने का काम किया था और आज तक होते-होते अभी पिछले बजट के अवसर पर यह घोषणा हुई कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम इस लाईन को लेंगे। हालांकि यह भी बात आई है कि प्रथम चरण में जो नई दूसरी और ली जायेंगी, उसमें रखने की भी बात हुई है, लेकिन यह तो पर्याप्त नहीं है महोदय। पर्याप्त इसलिए नहीं कि जादू की छड़ी से काम चलने वाला नहीं है, इसे कार्यरूप में परिणत होना है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा बिलरियागंज कस्बा है बहुत बड़ा, वहां पर स्कूल चलते हैं और जिसमें कि दूसरे मुल्कों से भी विद्यार्थी आते हैं। त्रानवीर है एक स्टेशन, वहां पर भी बगल में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि सारे अरबिक कंट्रीज से वहां पर आकर लड़के पढ़ते हैं। फिर उसके साथ राहुल जी की जन्मभूमि है। वहां पर दत्ता गुह है, दुर्बासा ऋषि, सब लोगों का आश्रम है और खरासों एक ऐसी जगह है, जो पुराने समय में रुई की बहुत बड़ी मंडी रही है और शिवली कालेज है—छः छः तो डिग्री कालेज हैं वहां पर—और शिवली कालेज ऐसा है कि उस जैसा कोई दूसरा कालेज शायद मेरी दृष्टि में तो नहीं दिखाई पड़ता है, वह बहुत बढ़िया कालेज है। लेकिन दुर्भाग्य से यह छोटी लाईन से बड़ी लाईन में परिवर्तित नहीं की जा सकी है। मंत्री जी जरा इधर ध्यान दीजिए, हमने आपसे पिछली बार, कई बार कहा है, अभी 15 दिन पहले भी मिलकर कहा है, जो बैठक हुई थी, उसमें भी कहा है, आपको पत्र भी लिखा था, जिस दिन कि बजट पेश हुआ। हम यह कहना चाहते है कि वहां के लोगों की यह अपेक्षा है और अब तो लोग कहते हैं कि आपकी सरकार हो गई, केन्द्र में आपकी सरकार हो, तब भी न हो तो बताइए हम लोग कहां जायेंगे, कहां रहेंगे आप जानते हैं कि कुछ राजनीति भी करनी पड़ती है और राजनीति इसलिए करनी पड़ती है कि वहां चुनाव होने वाले हैं, बहुत साफ बात मैं कह रहा

हूं कि चुनाव आ रहा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जोड़ दीजिए और इस सदन में इस बात की घोषणा कीजिए... **(व्यवधान)**

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : आज ही, नहीं तो वहां वापिस नहीं जाने देंगे।

**श्री राम नरेश यादव** : आप इस सदन को आज ही आश्वस्त करिए कि इस बजट में हम कुछ न कुछ धनराशि रखकर के इसके निर्माण के लिए रास्ता साफ करेंगे और पूर्वांचल के लोगों की जो अपेक्षा इतने दिनों से रही है, उसकी पूर्ति की दिशा में कदम उठायेंगे। नहीं तो एक बात जरूर है, मुझे भी बहुत तकलीफ है, मजबूर होकर के कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, हालांकि लोकतांत्रिक कदम ही उठाना पड़ेगा।

**श्री मोहम्मद मसूद खान** : (उत्तर प्रदेश) : हम लोग साथ देंगे।

**श्री राम नरेश यादव** : तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये, मसूद साहब कह रहे हैं कि हम भी साथ देंगे। आप फंड स्टेट से ले लीजिये कि आपने अपने ढंग से सदन में घोषित कर दिया। इसलिये आज ही और यहां से जो आप घोषणा करेंगे, पूरे पूर्वांचल के इलाके में ऐसी लहर दौड़ेगी कि लोग आपका स्वागत करने के लिये तैयार होंगे। हम यह भी कहेंगे कि आप दोनों लोग चलिये और वहां पर शिलान्यास करके आइये और एक वातावरण बनाने का काम करिये क्योंकि यह एक सांप्रदायिक सद्भाव जोड़ने की भी कड़ी होगी। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान दीजिये। आंख मत बन्द करियेगा, कान खुला रखियेगा और रखकर के इसकी घोषणा जरूर करियेगा नहीं तो हो सकता है कि हम जैसे लोगों को हमने बहुत पहले आंदोलन किये हैं, अब तो छोड़ दिये हैं लेकिन हो सकता है कि इस मामले को लेकर कोई जबर्दस्त आंदोलन वहां की जनता के बल पर करना पड़े, यह स्थिति नहीं जारी चाहिये।

नम्बर दो, उसी छोटी लाइन पर महोदय सरयू-जमुना है और भी दूसरी ट्रेनें हैं, आजमगढ़ से रिजर्वेशन था, लेकिन आजमगढ़ इतना अभागा हो गया कि सारा रिजर्वेशन कोटा कैंसिल, एक भी नहीं रह गया है। यही क्या हम लोगों को अपनी सरकार से लाभ मिलने वाला है ? इसलिये उस कोटे को भी पूरा कराइये। तीसरे, छोटी लाईन पर जो ट्रेनें चलती हैं। उसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वह तो होनी ही है और आपको एलान करना है। इसके बाद मैं यह कह रहा हूं कि ट्रेनों के डिब्बों में बाथरूम में इतनी गन्दगी, दुर्गन्ध होती है कि उसमें घुसते नहीं बनता है। आखिर जब आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ व्यवस्था करिये, कुछ सुधार लाइये। मान्यवर, सैकेंड क्लास के डिब्बे बढ़ाने की दिशा में भी ध्यान दीजिये, क्योंकि हमारे देश का नागरिक जब बाहर जाता है और उसके पास फर्स्ट क्लास में जाने के लिये इतने पैसे नहीं होते हैं और आखिर वह बेचारा जो गरीब है, अपने भाग्य का मारा हुआ है, जो साधारण नागरिक है और उन्हें सेकेंड क्लास के कम डिब्बे होने की वजह से जो परेशानी होती है, उसमें सुधार होना चाहिये। कभी-कभी देखिये, हमारे विदेश मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। देखा होगा कि सुलतानपुर में ट्रेनों की छतों पर काफी लोग सफर करते हैं। जितना अन्दर उतना ही बाहर छत पर हैं। लगता है कि उनके लिये यही अपर क्लास बन गया है। कभी-कभी वह सोचते हैं कि ऊपर वाली छत ही हमारे लिये फर्स्ट क्लास है।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : 4 टॉयर।

**श्री राम नरेश यादव** : यह जो स्थिति है बहुत ही दुखद स्थिति है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो ए.सी. फर्स्ट क्लास के और ए.सी.सेकेंड स्लीपर के जो डिब्बे बढ़ा रहे हैं, उनको कम करके जो हमारे दूसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले साधारण नागरिक हैं उनके लिये डिब्बों को बढ़ाने की व्यवस्था

[श्री राम नरेश यादव]

कीजिये, ताकि उनको भी लगे कि सरकार ने हमारे लिये कुछ किया है।

साथ ही साथ ट्रेनों में सफाई का मामला भी बहुत गंभीर है। अभी मैं कानपुर गया, वहां स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा वहां कोई भी जायेगा तो देखना पसन्द नहीं करेगा। इस तरह की जो स्थिति वहां प्लेट फार्म पर उनके बीच में, रेल पटरियों पर है वह भी बहुत चिन्ता का विषय बनी हुई है। आज जो प्लेट फार्म का टिकट बढ़ा रहे हैं मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं और करूंगा ही, लेकिन आप इस पर भी ध्यान दीजिये कि प्लेट फार्म का जो टिकट आपने बढ़ाया है उस पर गंभीरता से सोचिये और इसे कम कीजिये।

हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमारे रेल मंत्री जी अब आ गये हैं। अभी मैंने उनसे मिलकर भी कहा था और मीटिंग में भी कहा था। जो हमने रेल राज्य मंत्री जी से कहा है और आप उसका उत्तर भी देंगे। तो हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है और यह निवेदन और आग्रह हमारा ही नहीं है बल्कि जो वहां के लाखों लाखों गरीब लोग हैं और दूसरे जो लोग हैं, स्कूल और कालिजों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए आप आज सदन में घोषणा कीजिये, वैसे तो आपने घोषणा की है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में वह बनेगी और उसको फर्स्ट फेज में भी रखने जा रहे हैं। लेकिन जब यह मामला है तो आज ही सदन को आश्वास्त करके वहां की पूर्वांचल की जनता को बताने का काम करिये और वहां चलकर शिलान्यास भी करके सारा काम शुरू करा दीजिये। हम आपको बधाई देंगे और वहां के लोग भी आपको बधाई देंगे। आज जब आप एलान करेंगे तो वहां के लोग खुशी के मारे झूम उठेंगे कि जाफर शरीफ रेल मंत्री थे और जो काम आज तक नहीं हुआ था उस काम को उन्होंने करके दिखाया है। तो मुझे विश्वास है कि आप हम लोगों की भावनाओं का आदर करेंगे। इसलिये इसको प्रथम आधार पर लें और दूसरे आधार पर जो हमने अन्य सारी चीजें कही हैं, वह लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और फिर एक बार कहना चाहूंगा कि जो लोगों के चेहरों पर मुसकान नहीं है, जो उदास चेहरे हैं, हमारे बुनकर भी उदास हैं, आप जानते हैं कि बुनकरों की क्या स्थिति है, कहां कहां से लोग वहां पढ़ने के लिये आते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये जरा उन चेहरों पर मुस्कराहट लाने के लिये इस कदम को उठा लीजिये और यह बता दीजिये कि यहां आप आये थे और आपने ऐतिहासिक कदम पूर्वांचल के विकास के लिये शाहगंज से आजमगढ़ और मऊ, वैसे आजमगढ़ में तो कोई चीज बची नहीं है, न कोई उद्योग हैं, न आने-जाने का सही साधन है, रेह वाला, ऊसर वाला और सिंचाई का साधन भी नहीं है। इधर बलिया नजदीक है और शाहगंज जंक्शन है ही। इसलिये शाहगंज से शुरू कर दीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से मैं समझता हूं कि आप भी हमारा सहयोग करेंगे और मंत्री जी को निर्देश देंगे कि वे जरूर इस काम को करें।

**श्री मोहम्मद शफी खान** : मान्यवर, राम नरेश जी की इस बात की मैं ताईद करता हूं कि शाहगंज से मऊ तक जो छोटी लाइन है वह बड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाये। राम नरेश जी जब मुख्य मंत्री थे, हम और मालवीय जी केबिनेट मिनिस्टर थे, तब से ये ख्वाहिश है कि शाहगंज से मऊ तक बड़ी लाइन बन जाये। एक बात और कहना चाहता हूं... **(व्यवधान)**

**श्री जैपाल रेड्डी** (आंध्र प्रदेश) : आप तीनों कुलीग्ज राज्य सभा में आ गये **(व्यवधान)** आप तीनों एक पार्टी में क्यों नहीं आ जाते ?

श्री मोहम्मद मसूद खान : वह आंदोलन जब करेंगे तब हमारी पार्टी में आ जायेंगे ।

श्री राम नरेश यादव : ये मसला ऐसा है जिस पर हम लोग एक हैं ।

श्री मोहम्मद मसूद खान : महोदय, हरियाणा की जितनी स्ट्रैंथ है राज्य सभा की, जो किताब में दी है, उससे ज्यादा आजमगढ़ से राज्य सभा के मेंबर है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कम से कम शाहगंज से मऊ तक की छोटी लाइन बड़ी लाईन में तब्दील कर दी जाये । हमारे जिले आजमगढ़ के बारे में एक विद्वान शायर ने कहा है कि–

जिला अपना वतन-ख्वाही में मशहूरे जमाना है,

यहां का जर्रा-जर्रा जोश कौमी का फसाना है,

ये शिबली का वतन है, बोध जी का आस्ताना है

यहां का खित्ता सबसे आगे देश पर कुरबान होता है

यहां का नौजवान ब्रिगेडियर उस्मान होता है ।

ऐसे जिले में जिसने अपनी कुरबानी कश्मीर और हर जगह पर जाकर दी हैं, ऐसे जिले को नेग्लैंट करना मैं समझता हूं कि पूरे देश की तौहीन है । दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : इस तरह से नहीं कह सकते हैं आप दूसरी-तीसरी बात ।

श्री मोहम्मद मसूद खान : मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी रेलवे मंत्री जी किसी आफिसर को भेजें यह देखने के लिये कि जो हम लोगों को तकिया मिलता है बैड के साथ, हिन्दुस्तान का सारा जरासीम उसी तकिये में रहता है । उन सबकी तरफ आप ध्यान दें ।

उपसभाध्यक्ष : बात अच्छी है लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं ।

†شری محمد مسعود خاں: اتر پردیش! مانیور۔ رام نریش جی کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ شاہ گنج سے مئو تک جو چھوٹی لائن ہے وہ بڑی لائن میں پریورتت ہو جائے رام نریش جی جب مکھیہ منتری تھے۔ ہم اور مالویہ جی کیبنٹ منسٹر تھے تب سے یہ خواہش ہے کہ شاہ گنج سے مئو تک بڑی لائن بن جائے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔۔۔ مداخلت!۔۔

شری جے پال ریڈی: آپ تینوں کو لیکس واجپئی سبھا میں آ گئے۔۔ مداخلت!۔۔ آپ تینوں ایک پارٹی میں کیوں نہیں آ جاتے۔

شری محمد مسعود خاں: وہ آندولن جب کریں گے تب ہماری پارٹی میں آ جائیں گے۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

شری رام نریش یادو : یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر ہم لوگ ایک ہیں۔

شری محمد مسعود خان : مہودے ہریانہ کی جنتی آبادی ہے اتنے راجیہ سبھا کے جو کتابیں دی ہیں اس سے زیادہ اعظم گڑھ سے راجیہ سبھا کے ممبر ہیں۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کم سے کم شاہ گنج سے مئو تک کی چھوٹی لائن بڑی لائن میں تبدیل کر دی جائے۔ ہمارے ضلع اعظم گڑھ کے بارے میں ایک ودوان شاعر نے کہا ہے کہ۔

ضلع اپنا وطن خواہی میں مشہور زمانہ ہے
یہاں کا ذرہ ذرہ جوش قومی کا فسانہ ہے،
یہ شبلی کا وطن ہے۔ بودھ جی کا آستانہ ہے
یہاں کا خطّ سب سے آگے دیش پر قربان ہوتا ہے
یہاں کا نوجوان برگیڈیر عثمان ہوتا ہے

ایسے ضلع میں جس نے اپنی قربانی کشمیر اور ہر جگہ پر جا کر دی ہے ایسے ضلع کو نیگلیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پورے دیش کی توہین ہے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ۔۔۔ "مداخلت"۔

اپ سبھا ادھیکش • شری محمد سلیم" : اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں آپ دوسری تیسری بات۔

شری محمد مسعود خاں : میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ریلوے منتری جی کسی آفیسر کو بھیجیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہم لوگوں کو ٹکیہ ملتا ہے بیڈ کے ساتھ ہندوستان کا سارا جراثیم اسی ٹکیے میں رہتا ہے۔ ان سب کی طرف آپ دھیان دیں۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

اپ سبھا ادھیکش : بات اچھی ہے لیکن آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔

## MESSAGES FROM THE LOK SABHA

**(I) The Appropriation (Railways) Bill, 1993.**

**(II) The Appropriation (Railway) No. 2 Bill, 1993.**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

**(I)**

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) Bill, 1993, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 31st March, 1993.

2. The Speaker has certified that this Bill isa Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

**(II)**

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Apropriation (Railways) No. 2 Bill, 1993, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 31st March, 1993,

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy ofh each of the Bills on the Table.

†[] Transliteration in Arabic Script.